हैं और वे मूलत: सम्बंधित राज्य की वैज्ञानिक/तकनीकी जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाये जाते हैं। ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द में पाठ्यक्रम का विषय कृषि विश्वविद्यालयों आदि में विद्यमान पाठ्यक्रम से भिन्न होता है । उसमें विद्यार्थियों को ग्रामीण उत्पादक संगठनों के गठन और प्रबंध के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है और इन्हें स्वैच्छिक एजेंसियों का नाम दिया जाता है । इसमें मात्र कृषि की तुलना में बहुत व्यापक रेंज में विषयों की व्यवस्था है ।

(घ) जी हां । बोर्ड आफ गवर्नर्स के सदस्य बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और स्नातकों में से लिये जाते हैं ।

प्रयोगशाला से उपयोगशाला तक के कार्यक्रम

391. **डा. बापू कालदाते** : क्या कृषि मंत्री 7 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1308 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी शेष जिलों में कब तक एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) 116 प्रयोगशाला से उपयोगशाला तक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न संगठनों के तहत कौन-कौन से अन्य कार्य किये जा रहे हैं ; और

(ग) देश में दालों तथा तिलहनों के उन्नत किस्म के बीजों की कितनी-कितनी आवश्यकता है और ये कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध है इन बीजों की कितने एकड़ खेती बढ़ी है और इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन कितना बढ़ा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) आजकल देश में 89 कृषि विज्ञान केन्द्र है । प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयास किये जा रहे है । किन्तु धन-राशि के उपलब्ध न होने के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हो सकता है।

(ख) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम एक परिवारोन्मुख कार्यक्रम है । छोटे और सीमांत किसानों को तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से सहायता की जा रही है जिनमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, भेड़ पालन, खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन आदि जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं । अंतिम लक्ष्य नई प्रौद्योगिकियों को शुरू करके अपनाये गये परिवारों की आय बढ़ाना है ।

(ग) दालों और तिलहनों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और प्रयास यह किया जा रहा है कि अधिकाधिक क्षेत्र को नियोजित रीति से बीजों की सुधरी किस्मों के अन्तर्गत लाया जाय । सुधरी तिलहनों और दलहनों की आवश्यकता तथा उनकी उपलब्धता निम्न प्रकार है :—

(क्विंटल में)

क्रम सं०	वस्तु	सुधरे बीजों की आवश्यकता	सुधरे बीजों की उपलब्धता
1	तिलहनें	8.48 लाख	8.51 लाख
2	दालें	3.38 लाख	2.35 लाख

तिलहनों और दलहनों से सम्बंधित क्षेत्रफल और उत्पादन में हुई वर्षवार बढ़ोतरी निम्न प्रकार है जिसमें अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम का प्रभाव भी शामिल है :—

तिलहनों और दलहनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन :

वर्ष	तिलहन		दलहन	
	क्षेत्रफल (लाख हैक्टर)	उत्पादन (लाख टन)	क्षेत्रफल (लाख हक्टर)	उत्पादन (लाख टन)
1980–81 . . .	176.0	93.7	224.6	106.3
1981–82 . . .	189.1	120.8	238.4	115.1
1982–83 . . .	177.6	100.0	228.3	118.6
1983–84 . . .	186.9	126.9	235.4	128.9
1984–85 . . .	198.5	131.0	227.3	121.9

इस्पात-उत्पादन में आत्मनिर्भरता

392. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

डा. बापू कालदाते :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 14 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1935 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की नीति की जो जांच की जा रही है, उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ख) इस्पात के उत्पादन की किस्म को सुधारने में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ; और

(घ) क्या जापान द्वारा इस्पात उत्पादन के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रौद्योगिकी को अपने देश में भी अपनाया जा सकता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत): (क) "सेल" के कारखाने वर्ष 1984-85 से विक्रय इस्पात की क्षमता के उपयोग को 73 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 1985-86 में 79 प्रतिशत तक करने में सक्षम हो गये हैं। वर्ष 1986-87 के दौरान विक्रेय इस्पात की क्षमता के उपयोग को बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक करने की योजना है । आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा आयात को कम करने के उद्देश्य से इस्पात के देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक रणनीति अपनायी जाएगी ।

(ख) क्वालिटी में सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । 14 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं. 1935 के उत्तर में उल्लिखित इस्पात की क्वालिटी में सुधार लाने के लिये सुझाये गये विभिन्न उपाय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । वर्ष 1985-86 में "सेल" ने अपने इस्पात की किस्म में और सुधार किया है ।

(ग) सातवीं योजना के दौरान बोकारो, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों को आवंटित पूंजीगत व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है : —

(करोड़ रुपये)

	सातवीं योजना के लिए आवंटन	वर्ष 1986–87 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 1985–86 के लिए खर्च (आंकड़े अस्थायी हैं)
बोकारो . . .	774.01	121.56	145.16
दुर्गापुर . . .	688.03	79.00	43.03
राउरकेला . . .	674.20	74.50	87.12